बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि — 25 फाल्गुन, 1939 (श.) / 16 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 19

1.	शिक्षा विभाग	-	-	17
2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	02
			कुल योग –	19

राशि की उपलब्धता

109. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरान्त निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त राज्य के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों/उच्च मा.वि. (इन्टर महा.) के शैक्षणिक सत्र 2010-11 से 2012-13 के वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3,37,49,16,400/- रु. (तीन अरब सैंतीस करोड़ उनचास लाख सोलह हजार चार सौ रुपये) की स्वीकृति एवं तत्काल 3,30,00,00,000/- रु. (तीन अरब तीस करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि इस स्वीकृत राशि की कार्रवाई विभाग, बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों की उदासीनता के कारण विद्यालयों को प्राप्त नहीं हो सकी है जिससे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि कबतक खंड 'क' में वर्णित राशि को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

कर्मियों का वेतन

110. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत संत विनोबा उच्च विद्यालय तीनटेंगा दियारा का अधिग्रहण हो चुका है लेकिन उससे संबंधित प्रक्रिया आज की तिथि में भी लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि इसी विद्यालय के साथ-साथ राज्य के अन्य दो विद्यालयों का भी अधिग्रहण हुआ है जो उक्त स्थिति में ही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वहां कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन कबतक शुरू करना चाहती है;

शिक्षकों को प्रशिक्षिण

111. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) क्या यह सही है कि 2019 तक ही केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी कि अभी तक उसने कितने अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है और कितने शिक्षक अभी भी अप्रशिक्षित हैं और उन्हें कबतक प्रशिक्षित करने की योजना है?

शिक्षक संख्या में बढ़ोत्तरी

112. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अभी भी करीब 1500 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरप्लस शिक्षकों वाले स्कूलों की संख्या कम है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कैसे और कबतक?

वेतनमान का निर्धारण

113. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि उप सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक 2153 की कंडिका (3) एवं कंडिका (6) में विरोधाभास होने के कारण वार्षिक इंक्रीमेन्ट पर विवाद है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है, ताकि सातवें वेतनमान का निर्धारण हो सके, यदि हां तो कबतक?

पद का सृजन

114. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के आलिम और फाजिल स्तर के 118 मदरसों में बिना शिक्षक बी.ए. और एम.ए. डिग्री स्तर के छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि परीक्षा संचालन की जवाबदेही मदरसा बोर्ड से अलग कर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को दी गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि आज तक उन मदरसों में न तो शिक्षकों के पद सृजित किये गये हैं और न ही किसी भी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के लिये शिक्षकों के पद सृजित कर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है?

विद्यालय की मरम्मती

115. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर बाजार में मोहिउद्दीन नगर 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की अत्यधिक संख्या के कारण एक दिन छात्र दूसरे दिन छात्रा पुन: तीसरे दिन छात्र, चौथे दिन छात्रा, पुन: पांचवें दिन छात्र, छठे दिन छात्रा अर्थात केवल तीन दिन ही पढ़ाई हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' के विद्यालय कोष में पन्द्रह लाख से भी अधिक की राशि उपलब्ध है;

(घ) क्या यह सही है कि विद्यालय का पुराना भवन बहुत ही जर्जर हो गया है जिसकी मरम्मती हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, समस्तीपुर से बार-बार अनुरोध करने पर भी निर्माण के प्राक्कलन की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विद्यालय विकास से मरम्मती की स्वीकृति विकास निधि से कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सहायता राशि

116. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 31 अगस्त, 2010 को जिलाधिकारियों की जांचोपरांत करीब 300 संस्कृत स्कूलों को कैबिनेट द्वारा वित्त सहित स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं चालू वित्तीय वर्ष के सात महीनों के वेतन के लिए करीब रु. 18 करोड़ 27 लाख 23 हजार निर्गत किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी इन 300 संस्कृत विद्यालयों को सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित स्कूलों को अविलम्ब सहायता राशि प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

खेल कैलेंडर

117. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि स्कूलों में खेल के लिए वार्षिक कैलेंडर बनाया गया है, इसमें 33 गेम हैं, हर उम्र के बच्चों के लिए गेम है;

(ख) क्या यह सही है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल कैलेंडर के पालन में स्कूल रुचि नहीं दिखाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्कूलों में खेल के लिए वार्षिक कैलेंडर का पालन करने एवं स्कूल प्रशासन द्वारा कोताही बरतने पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कैसे, नहीं तो क्यों?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

118. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट की 14 प्रतिशत राशि शिक्षा पर व्यय करती है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त वर्णित व्यय के बावजूद राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, फलत: निजी संस्थान फल-फूल रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में कौन-कौन-से उपाय करना चाहती है?

अध्यक्ष की नियुक्ति

119. **डा. मदनमोहन झा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्षों से बिहार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि अध्यक्ष पद रिक्त रहने के कारण छात्रों एवं शिक्षकों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रभारी अध्यक्ष द्वारा कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है, जिससे छात्रों एवं शिक्षकों में काफी आक्रोश व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियुक्ति अनुमोदन

120. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली, बिहार नगर निकाय नियमावली एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त संशोधित नियमावली 2012) के अनुसार अल्पसंख्यक (प्रबंध समिति नियंत्रणाधीन) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए एस.टी.ई.टी. पात्रता भी अनिवार्य कर दी गयी है जबकि अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी विद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया में समानता नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि धारा-23 एवं 30(1) के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों के आलोक में आर.टी.ई. ऐक्ट 2009 के प्रावधान में अल्पसंख्यक संस्थानों में प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है तथा एन.सी.टी.ई. उच्च न्यायालय, पटना, झारखंड, मद्रास एवं उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने भी अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं मानने का आदेश निर्गत किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की बाध्यता को खत्म कर अल्पसंख्यक विद्यालयों (+2) शिक्षकों की नियुक्ति अनुमोदन करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

वेतन वृद्धि

121. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों में बहाल नियोजित शिक्षकों को आजतक मात्र 11,000/- रुपये नियत वेतन दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प में यह कहा गया था कि इन्हें भी राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के समान वेतन दिया जाएगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संस्कृत एवं मदरसा में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की वेतन वृद्धि करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

वेतन विसंगति

122. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 1632, दिनांक 21.06.2017 के द्वारा वेतन निर्धारण में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के वेतन निर्धारण में क्रमश: 8640, 5690 का अन्तर होता है;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक वेतन निर्धारण के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनने से राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वेतन विसंगतियों का निराकरण करना चाहती है?

विद्यालय का निर्माण

123. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत प्रखंड अस्थावां के ग्राम-अमरसिंह बिगहा में प्राथमिक विद्यालय में लगभग 500 छात्र-छात्राएं पांचवीं कक्षा तक अध्ययनरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वर्णित विद्यालय में भूमि की उपलब्धता होने के बावजूद मात्र एक कमरे में पठन-पाठन हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

सेवा मान्यता

124. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 84-85 प्रोजेक्ट विद्यालयों में 1989 से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षकों को सेवा मान्यता दी गई है और वेतनादि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उन विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा की मान्यता नहीं दी गई है, जबकि न्यायालय के आदेशानुसार सेवा मान्यता के उपरान्त प्रशिक्षण कर लेना है;

(ग) क्या यह सही है कि महिला एवं उर्दू अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा की मान्यता दी गई है लेकिन एक सौ से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को आज तक सेवा मान्यता नहीं दिये जाने के कारण वर्षों से कार्यरत वैसे शिक्षक और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा मान्यता देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नए भवन का निर्माण

125. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की हजारों की संख्या है जहां कमरों के अभाव के कारण केवल तीन-तीन दिन ही छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' के विद्यालय में सरकार द्वारा स्वीकृत 10+2 का दो मंजिला भवन अबतक नहीं बना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनने वाले नये भवन का शीघ्र निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नाट्य विद्यालय की स्थापना

126. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के रंगकर्मियों की राज्य में नाट्य विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कलाकारों ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी के पास अपनी गुहार लगाई है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एन.एस.डी.), दिल्ली की तर्ज पर बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा (बी.एस.डी.) की स्थापना से राज्य में नाट्य प्रतिभाओं का पलायन रुकेगा। फिलहाल राज्य के सक्रिय व समर्थ रंगकर्मी देश के अन्य राज्यों में नाट्य प्रशिक्षण का कोर्स करने जा रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दिल्ली की तर्ज पर बिहार में बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा (बी.एस.डी.) खोलने पर विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति

127. **डा. मदन मोहन झा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार का एकमात्र केन्द्रीय पुस्तकालय, सिन्हा लाईब्रेरी, पटना में स्थायी पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति विगत 20 वर्षों से लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि राजाराम मोहन राय फाउण्डेशन से प्रति वर्ष मिलने वाली करोड़ों की अनुदान राशि पुस्तक की खरीद नहीं होने से विगत 8 वर्षों से सरेंडर हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तक क्रय मद में राज्य सरकार ने अनुदान राशि बंद कर रखी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय में अविलंब अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए अनुदान राशि मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 16 मार्च, 2018